# मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद भी 6 महीने से पासपोर्ट कार्यालय में लटक रहा ताला

**17 लाख के पासपोर्ट कार्यालय बनने के बाद भी 300 किलोमीटर जाना मजबूरी**

जगदलपुर 26 जुलाई (दण्डकारण्य समाचार)। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। बीते 6 महीने में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन की राह पर चलते हुए छत्तीसगढ़ में कई अहम निर्णय व घोषणाएं की गई हैं, लेकिन बस्तर के संभाग मुख्यालय स्तिथ कलेक्ट्रेट में 17 लाख रूपये की लागत से पासपोर्ट कार्यालय मुख्यमंत्री के हाथों उद्धघाटन के 6 महीने बाद भी शुरू नहीं होनें से लोग निराश है। प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनें के बाद भी बस्तर के लोगों को पासपोर्ट कार्यालय की सुविधा नहीं मिल रही है। लोगों को अब भी पासपोर्ट बनवाने के लिए राजधानी रायपुर का सफर तय करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा पासपोर्ट कार्यालय का उद्धघाटन के बाद लोगों को




थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन पासपोर्ट अधिकारी नहीं पहुंचने के कारण भवन में ताला जड़ा हुआ है। उद्धघाटन के बाद भी पासपोर्ट कार्यालय शुरू नहीं होने से लोग चुनावी फंडा बता रहें है। बस्तर संभाग के सातों जिले के लोग फिलहाल राजधानी रायपुर जाना मजबूरी हैं। इन्हें 300-500 किलोमीटर लंबी यात्रा के साथ ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है। पासपोर्ट के लिए जिस दिन डेट मिलती है, अगर उस दिन काम नहीं हो पाया, तो नई तारीख के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में बार-बार ट्रैवल का खर्च बढ़ने के साथ ही समय भी लगता है।

### 3500 और 1500 में तैयार होंगे पासपोर्ट

पासपोर्ट तैयार करने के लिए जो शुल्क रापुर स्थित कार्यालय में लिया जा रहा है वह जगदलपुर में भी केंद्र खुलने पर लागू रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार अभी रायपुर में पासपोर्ट तीन दिन में चाहने पर 3500 रुपए लिए जा रहे हैं. वहीं 15 दिन की प्रक्रिया के लिए 1500 रुपए लिए जा रहे हैं। 3 दिन में वही पासपोर्ट तैयार होता है जिसके लिए काई विशेष कारण हो। पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन सबसे जरूरी है।

### पासपोर्ट अधिकारी नहीं पहुंचने से लटका मामला

पासपोर्ट ऑफिस के लिए नेटवर्क क्लीयरेंस मिल गया है। ट्रेनिग भी हो गया है। पासपोर्ट कार्यालय का एक और पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी सेवाएं देंगे। बस्तर सभी तकनीकि आवश्यकताओं के साथ भवन निर्माण पूरा हो गया है। चुनाव सम्पन्न हो गया है। लेकिन केंद्र सरकार की और से पासपोर्ट अधिकारी नहीं पहुंचने के कारण ताला लटक रहा है। अधिकारी आने के बाद ही पासपोर्ट कार्यालय शुरू हो जाएगा।

# स्थानीय वन उत्पाद की प्रोसेसिंग को दी जाए प्राथमिकता - कलेक्टर

**बाबू सेमरा स्थित ट्राइफेड कार्यालय में अधिकारियों से कलेक्टर ने की चर्चा**

जगदलपुर, 26 जुलाई जुलाई (दण्डकारण्य समाचार)। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने गुरुवार की सुबह बाबू सेमरा में स्थित ट्राइफेड कार्यालय और प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना का निरीक्षण कर ट्राइफेड के अधिकारियों से चर्चा की। कलेक्टर विजय ने कहा कि ट्राईफेड के इस प्रोसेसिंग यूनिट में बस्तर के स्थानीय वन उत्पाद और मार्केट की उपलब्धता के आधार पर उत्पाद का प्रोसेस करने में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने बस्तर में बहुतायत में मिलने वाले इमली, महुआ, मिर्ची, आम और काजू की प्रोसेसिंग करने की सलाह दी। साथ ही संस्था को जल्द संचालित कर को लोगों को रोजगार के अवसर देने भी कहा। इसके अलावा उन्होंने ट्राइफेड यूनिट में लगाए जा रहे मशीनों के संचालन हेतु प्रशिक्षण देने, तकनीकी सहयोग, मशीनों का मरम्मत का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे, ट्राइफेड के डिप्टी जनरल मैनेजर श्रीमती ममता शर्मा, असिस्टेंट मैनेजर डा. जेबा जमील, रीजनल मैनेजर पीएम खदाने सहित प्रोजेक्ट के कंसलटेंट अधिकारी उपस्थित थे।

ट्राइफेड के अधिकारियों ने लगाए जा रहे यूनिट की जानकारी देते हुए बताया कि यूनिट में प्रोसेसिंग, फूड ड्राय, विनेगर, मिक्सिंग, बॉलिंग के यूनिट लगाए गए हैं। ट्राइफेड के अधिकारी दिल्ली से यूनिट स्थापना को प्रारंभ करवाने के सिलसिले में पहुंचे थे। उन्होंने संस्था की अन्य आवश्यकता पर कलेक्टर से विस्तृत चर्चा की।

# बस्तर विश्वविद्यालय अध्ययन शाला के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 31 जुलाई तक मिलेगा प्रवेश

- **न्यूनतम फीस से हासिल कर सकेंगे यूजी एवं पीजी की डिग्री**
- **नवपदस्थ कमिश्नर बस्तर ने अंदरूनी ईलाके के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु दाखिला करवाने दिए निर्देश**

जगदलपुर, 26 जुलाई (दण्डकारण्य समाचार)। बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर द्वारा पहली बार अपने विश्वविद्यालय के अध्ययन शाला में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से बीए, बीएससी, बीकॉम सहित एमए, एमएसी एवं एमकॉम में सीधे प्रवेश की सुविधा प्रदान किया जा रहा है। प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राएं न्यूनतम 975 रुपए शुल्क में ग्रेजुएशन और 3650 रुपये के शुल्क में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जिसमें कोई भी छात्र-छात्रा सीधे विश्वविद्यालय आकर 31 जुलाई 2024 तक प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश से संबंधित समस्त जानकारी विश्विद्यालय की वेबसाइट द्धह्लह्लश्चह्य~//ह्यद्बद्म1ड्डद्वह्लड्डह्म्.ड्डष्.द्बठ्ठ पर देखी जा सकती है। बस्तर अंचल के अंदरूनी ईलाके के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से अलग-अलग छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही छात्र-छात्राओं की अध्ययन के प्रति रूझान को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए 24म7 लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 87122-27321 या 87122-29289 अथवा ई-मेल पर सम्पर्क कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि राज्य शासन द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय को 20 नवीन शिक्षण विभागों में 33 नवीन स्नात्तक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही भारत सरकार द्वारा बस्तर विश्वविद्यालय को पीएम उषा (मेरु) बहुविषयी शिक्षा एवं शोध योजनांतर्गत अनुदान भी स्वीकृत किया गया है। उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को बहुविषयक शिक्षा आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन एवं सभी अध्ययनशाला में महत्वपूर्ण विषयों पर शोध को भी प्रारंभ किया गया है।

बस्तर यूनिवर्सिटी मेरू विश्वविद्यालय होने के कारण सम्पूर्ण बस्तर अंचल के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के युवाओं को अपने अध्ययनशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं युवाओं के रुचिकर व्यवसाय एवं रोजगार चुनने का अवसर प्रदान करना चाहता है। लेकिन वर्तमान में बस्तर क्षेत्र की उच्च शिक्षा में ग्रास इनरोलमेंट रेशियो (जीईआर) लगभग 11 प्रतिशत है, जो कि बहुत कम है। इसे मद्देनजर रखते हुए नवपदस्थ कमिश्नर बस्तर संभाग डोमन सिंह ने बस्तर विश्वविद्यालय के उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सभी शासकीय एवं गैर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में सत्र 2023-24 के तहत कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में कक्षा बारहवी उत्तीर्ण करने वाले समस्त छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में प्रवेश हेतु मार्गदर्शन कर उच्च शिक्षा हासिल करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के निर्देश सयुंक्त संचालक स्कूल शिक्षा और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही बस्तर संभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं गैर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के समस्त प्राचार्यों के माध्यम से इस दिशा में अंदरूनी ईलाके के विद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु प्राथमिकता के साथ अभिप्रेरित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

# कलेक्टर ने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक की मृत्यु उपरांत वारिसान को सौंपा नामांतरण पत्र

- **वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वारिसानों के नाम पर एफआरए पत्र का नामांतरण करने की जा रही कार्यवाही**

जगदलपुर, 26 जुलाई जुलाई (दण्डकारण्य समाचार)। राज्य शासन के निर्देशानुसार व्यक्तिगत वन अधिकारों के अधिकार अभिलेखीकरण तथा वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिसानों को अधिकार हस्तांतरण संबंधित कार्यवाहीके परिपालन में कलेक्टर विजय दयाराम के. मार्गदर्शन में सभी तहसील में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिसानों को अधिकार हस्तांतरण संबंधित कार्यवाही किया जा रहा है। कलेक्टर श्री विजय ने बुधवार को जगदलपुर अनुभाग के वन अधिकार पत्रधारक सरगीपाल निवासी जगबंधु की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिसान पत्नी डोमानी जगबंधु को वनाधिकार पत्र वितरण किया। इसी प्रकार सभी तहसील में बुधवार को दो-दो वारिसान को एफआरए पत्रक वितरण किया गया। जिले में इस प्रकार के लगभग तीन हजार 800 प्रकरण है। गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2008 से लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को काबिज भूमि पर वन अधिकारों की मान्यता प्रदाय करना है, ताकि उनके भूमि का विवरण शासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जा सके और इसके साथ ही उन्हें काबिज भूमि के अधिभोग का अधिकार प्रदाय किया जा सके, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही स्थानीय समुदाय के माध्यम से वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन को सुदृढ़ करते हुए परिस्थितिकीय संतुलन भी बनाये रखना है। वन अधिकार नियम, 2007 एवं संशोधित नियम 2012 के प्रावधान 12 (क) (9) के अनुसार हक जारी करने की प्रक्रिया पूरी होने पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग इस प्रकार निहित वन भूमि का अंतिम मानचित्र तैयार की जाएगी और संबद्ध प्राधिकारी इस प्रकार निहित वनाधिकारों को यथास्थिति राजस्व और वन विभाग के अभिलेखों में सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिलेख अद्यतन किया जा रहा है इसके साथ ही अधिनियम की धारा-4 की उपधारा 4 (1) अनुसार यह अधिकार वंशानुगत होगा। अधिनियम की धारा-4 की उपधारा 4 (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार वंशानुगत होगा, किन्तु संक्रमणीय या अन्तरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति-पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में रजिस्ट्रीकृत होगा तथा सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशागत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जाएगा। राज्य में जारी व्यक्तिगत वन अधिकारों के अधिकार अभिलेखीकरण तथा वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिसानों को अधिकार हस्तांतरण संबंधित कार्यवाही, अन्य भूमि संबंधित कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रक्रिया राज्य शासन की समसंख्यक अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है।

# टपकते पानी में पढ़ने को मजबूर आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चे

जगदलपुर 26 जुलाई (दण्डकारण्य समाचार)। शहर के निकटस्थ ग्राम पंचायत बुरूंदबाड़ा स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र की छत क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे बारिश होने पर कमरे में बारिश का पानी टपकता रहता है।

नगर से लगभग 8-9 किलो मीटर दूर ग्राम पंचायत बुरूंदबाड़ा स्थितं आंगनबाड़ी केन्द्र की पक्की छत जर्जर हो गई है जिससे बारिश का पानी कमरों में टपकता रहता है ओर कमरे का फर्श पूरी तरह गीला हो जाता है।

बच्चों को बैठने तक की जगह नहीं बचती है। बारिश तेज होने से बच्चे गीले हो जाते है। कमरे में टपकते पानी से बचाने विद्यार्थियों को समीप के ग्रामीण बैंक में ले जाकर बिठाया जाता है।

शाला के छत के सुधार के लिए संबंधित विभाग में सूचना दी गई है लेकिन अब तक छत का सुधार नहीं किया गया है।

आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिका श्रीमती सोमरा ने बताया कि कमरे में बारिश का पानी टपकने से कमरा गीला हो जाता है, जिससे बच्चों का बैठना मुश्किल हो जाता है। छत सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

# जंगल में बोड़ा एवं मशरूम बीनने में जुटी हैं ग्रामीण महिलाएं

जगदलपुर 26 जुलाई (दण्डकारण्य समाचार)। शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से लगे जंगलों में ग्रामीण महिलाएं सुबह से बोड़ा छाती बिनने में लग जाती है, जिसकी बिक्री कर लाभ कमा रही है।

गर्मी हो या बरसात ग्रामीण महिलाएं बारहों महीने जंगल या आसपास क्षेत्रों से वनोपज का संग्रहण कर हाट बाजारों में बिक्री कर आय अर्जित करती है। बरसात के इन दिनों में धुरगुड़ा, तूरेनार, कुरंदी, आसना सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रो में ग्रामीण महिलाएं एवं युवतियॉ सुबह से आसपास के जंगल में छाती (मशरूम) एवं बोड़ा बीनने में लग जाती है। बोड़ा एवं मशरूम एकत्रित कर शहर के



बाजार या आसपास के हाट बाजारों में बेचकर अच्छी आय अर्जित कर रही है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इन दिनों धान रोपाई में लगभग 2 सौ रूपये दिन मजदूरी मिल रहा है लेकिन हम उससे पहले सुबह 10-11 बजे तक 5-7 सौ रूपये तक का बोडा या मशरूम एकत्रित कर बेच देते है।

# थामाकोनी में हैण्डपंप खराब, गांव में पेयजल संकट

जगदलपुर 26 जुलाई (दण्डकारण्य समाचार)। शहर के निकटस्थ ग्राम पंचायत आसना के आश्रित गांव थामाकोनी में हेण्डपंप खराब हो गया है, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से जुझना पड़ रहा है। इधर उधर से ग्रामीण पानी की व्यवस्था करने को मजबूर है।

ग्राम पंचायत आसना के आश्रित ग्राम थामाकोनी में लगे हेण्डपंप से भरपूर पानी आ रहा था । गर्मी के दिनों में बच्चे दिन भर उसमें नहाना धोना करते रहे है। हेण्डपंप का पानी मार्ग में भी भरता रहा है लेकिन विगत 1-2 माह से हेण्डपंप से पानी आना बंद हो गया है, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सालों से हेण्डपंप की सफाई नहीं हुई है। वहीं हेण्डपंप में खराबी



आने से सुधार भी नहीं किया गया है जिससे गांव के लोगों को पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है।

# अग्निवीर वायु भर्ती हेतु 28 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित

जगदलपुर, 26 जुलाई (दण्डकारण्य समाचार)। भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु भर्ती हेतु अविवाहित युवक एवं युवतियों से 28 जुलाई 2024 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। अग्निवीर वायु भर्ती के तहत कम्प्यूटर परीक्षा 18 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगी। अग्निवीर वायु हेतु अविवाहित उम्मीदवार का जन्म 03 जुलाई 2004 और 03 जनवरी 2008 (दोनों तिथियों सम्मिलित) के मध्य हुआ हो। आवेदक केन्द्रीय, केंद्र शासित अथवा राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट 102 अथवा समकक्ष परीक्षा में कुल योग का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं अंग्रेजी विषय में 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हो। पुरुष आवेदकों की न्यूनतम ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर एवं महिला आवेदकों की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। आवेदक का वजन ऊंचाई एवं उम्र के अनुरूप होना आवश्यक है। पुरुष आवेदकों हेतु सीना 77 सेंटीमीटर तथा 05 सेंटीमीटर का विस्तार आवश्यक है। महिला आवेदकों हेतु सीना शारीरिक बनावट के अनुरूप तथा 05 सेंटीमीटर का विस्तार आवश्यक है। अग्निवीर वायु हेतु पंजीयन के लिए आवेदक स्वयं अथवा किसी भी च्वाईस सेंटर के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर पंजीयन किया जा सकता है। इसके अलावा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जगदलपुर में भी पंजीयन की व्यवस्था की गई है।

# विकास, नवाचार और गरीब कल्याण के साथ विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूत करने वाला बजट

जगदलपुर, 26 जुलाई (दण्डकारण्य समाचार)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.ह्र कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। प्रदेश प्रवक्ता संजय पाण्डेय ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत 2047 को लेकर जो रोडमैप बनाया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उस अनुरूप ही रोजगार, कौशल विकास, व्यापार-उद्योग जगत तथा मध्यम वर्ग के लिए आगे बढ़ने के शानदार अवसर प्रस्तुत किए हैं। गरीबों के लिए जहां मुफ्त राशन योजना जारी रखने की घोषणा की गई है, वहीं महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान कर केंद्र सरकार ने महिला वर्ग के उत्थान और आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण के अपने संकल्प को मज़बूती प्रदान की है। बजट में जनजातीय उन्नत् ग्राम अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार की आदिवासियों के उत्थान के संकल्प को प्रदर्शित करता है, जिससे देशभर के 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे।

बजट में युवाओं के लिए की गयी घोषणाओं को रेखांकित करते हुए संजय पाण्डेय ने कहा की कि सरकार ने टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की घोषणा की है। सरकार की इंटर्नशिप योजना से 1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा. इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान 5000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं सरकारी इंटर्नशिप योजना के तहत कंपनियां अपने सीएसआर फंड से प्रशिक्षण लागत वहन करेंगी। सरकार के इस कदम से युवा वर्ग को निश्चित रूप से करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी को ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया है। बजट में एमएसएमई सेक्टर में 100 करोड़ रुपए का जो ऋण दिया गया है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। स्टार्टअप को बढ़ाने, ई कॉमर्स हब बनाने, उसमें टैक्स को लेकर जो घोषणा की गई है वो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा।